चीन ने जनसंख्या नीति बदली

हाल ही में चीन ने अपनी दशकों पुरानी जनसंख्या नीति में आमूल परिवर्तन किया है। पिछले कई वर्षों से चीन एक-संतान नीति का सख्ती से पालन करता रहा है और एक से ज़्यादा संतान होने पर दंड की व्यवस्था भी थी। यह नीति क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट *लिमिट्स टू ग्रोथ* के इस निष्कर्ष पर टिकी थी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

इस व्यवस्था में सबसे पहले 2012 में बदलाव किया गया था जब कुछ दम्पतियों को दूसरी संतान पैदा करने की पात्रता दी गई थी। दूसरी संतान के लिए पात्रता की शर्त यह रखी गई थी कि दोनों में से कम से कम एक अपने माता-पिता की इकलौती संतान हो। अब संभवतः एक-संतान नीति को उतनी सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा हालांकि शायद दम्पतियों को दूसरी संतान के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी।

जनसंख्या नीति में उपरोक्त परिवर्तन मूलतः जनसंख्या की संरचना में हो रहे प्रतिकूल परिवर्तनों के मद्देनज़र किया गया है। एक-संतान नीति का सबसे प्रमुख असर तो यह रहा है कि लिंग-आधारित गर्भपातों में बहुत वृद्धि हुई है। भारत के ही समान चीन में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा काफी बलवती है। लिंग पता करने के बाद गर्भपात का मतलब है कन्या भ्रूण हत्या। इस रुझान का परिणाम यह हुआ है कि चीन की आबादी में लड़कियों-महिलाओं की संख्या में भारी कमी आई है। 2010 की जनगणना के मुताबिक चीन में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या मात्र 847 थी। सामान्य स्थिति में जितनी लड़कियां होना चाहिए थीं, उनमें से पूरी 6.2 करोड़ लड़कियां नदारद थीं। एक अनुमान के मुताबिक यदि रातोंरात चीन में जन्म लेने वाले बच्चों का लिंग अनुपात सामान्य हो जाए, तो भी 2050 में कम से कम 10 प्रतिशत लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी।

एक-संतान नीति का दूसरा परिणाम यह हुआ है कि चीन की आबादी में बुज़ुर्गों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। इसका मतलब है कि काम करने वाले लोग कम हैं। देश की करीब 12 प्रतिशत आबादी 60 से ऊपर के लोगों की है। इसका असर चीन के आर्थिक विकास पर पड़ रहा है।

दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक-संतान नीति में ढील देने का जो फैसला किया है वह मूलतः आर्थिक विकास की धीमी होती रफ्तार से चिंतित होकर ही लिया गया है। मगर कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह से सरकारी नीतियां बदलकर खास कुछ हासिल नहीं होगा। आजकल के युवा वैसे भी एक से ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते क्योंकि बच्चे पालना बहुत महंगा हो गया है। जब 2013 में एक-संतान नीति में कुछ शर्तों के अधीन छूट दी गई थी तब भी कुल पात्र दम्पतियों में से मात्र 6 प्रतिशत ने ही इसका फायदा उठाने के लिए आवेदन दिए थे। विशेषज्ञ कहते हैं कि आज का चीन एक-संतान समाज हो चुका है और नीति बदलने से इस सोच में ज़्यादा परिवर्तन आने की गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लोगों के प्रजनन पर नियंत्रण पूरी तरह समाप्त होना चाहिए, अन्यथा जनसंख्या में विसंगतियां पैदा होती ही रहेंगी। ***(स्रोत फीचर्स)***